शुक्रवार, 5 जून 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

विराट कोहली और फैंस को लगा करारा झटका

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

सेंसर बोर्ड के सबसे चर्चित अध्यक्ष तक का सफर

Page-05

मामले में गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब उससे भवन की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन मानकों और होटल संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर पूछताछ कर रही है।

दिल्ली अग्निकांड में बड़ा खुलासा

छत का रास्ता बंद था,मालिक चार दिन की रिमांड पर

दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी क्षेत्र में स्थित गेस्ट हाउस में हुए भीषण अग्निकांड की जांच में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार हादसे के समय भवन की छत तक जाने वाला रास्ता बाहर से बंद था, जिसके कारण कई लोग आग और धुएं से बचने के लिए खिड़कियों से बाहर कूदने को मजबूर हो गए।इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई थी।मामले में गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश बजाज को साकेत कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब उससे भवन की सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन मानकों और होटल संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि हादसे के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था और लंबे समय तक अपने घर भी नहीं पहुंचा।पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में लवकेश बजाज ने बताया कि उसने करीब

तीन वर्ष पहले यह भवन खरीदा था। भवन पहले एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में इस्तेमाल होता था और बाद में इसे गेस्ट हाउस के रूप में संचालित किया जाने लगा। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि भवन में आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। पुलिस को संदेह है कि अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से भवन में निर्धारित क्षमता से अधिक कमरे तैयार किए गए थे। आरोप है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर अतिरिक्त निर्माण कराया गया, जिससे आपात स्थिति में लोगों के निकलने के रास्ते प्रभावित हुए। लवकेश बजाज ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि होटल संचालन के अधिकांश कार्य स्टाफ के जिम्मे थे और वह स्वयं नियमित निगरानी नहीं करता था। यह हादसा राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

इंडिगो ने अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो ने अपने अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। कंपनी ने कम डिमांड, बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन खर्च और अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गों पर जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कई विदेशी देशों के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से लंगकावी, क्राबी, हो ची मिन्ह सिटी, हांगकांग और शंघाई के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी जाएंगी। वहीं सिएम रीप के लिए उड़ानों का संचालन 3 जुलाई 2026 से रोका जाएगा। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और इसके बाद 1 अक्टूबर से इन मार्गों पर बुकिंग दोबारा शुरू करने की योजना है। इसके साथ ही ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर के लिए शुरू की गई सेवा भी फिलहाल बंद की जाएगी। इंडिगो का कहना है कि हर साल जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कुछ रूट्स पर क्षमता घटाने का फैसला लिया गया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन को संतुलित रखा जा सके और बाकी नेटवर्क पर सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें। हालांकि इन रूट्स पर उड़ानें रोकी जा रही हैं, लेकिन एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि वह अभी भी हर सप्ताह 1,800 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर रही है।

वायरल वीडियो के बाद दो सुरक्षाकर्मी हिरासत में

बिहार की राजधानी पटना स्थित खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर हुए विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। वीडियो में कथित तौर पर कुछ लोगों को हवाई फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति खान सर के निजी सुरक्षा कर्मी हैं।यह पूरा मामला दो जून की रात का बताया जा रहा है, जब मुसल्लहपुर हाट क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना हुई थी। शुरुआती तौर पर इसे एकतरफा हमला माना जा रहा था, लेकिन वायरल वीडियो ने जांच की दिशा बदल दी है। वीडियो में दो लोग हथियार लोड करते और उसके बाद हवा में कई राउंड फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं।वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस की एक टीम खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति यही हैं या कोई अन्य।पुलिस वीडियो की तकनीकी जांच भी करवा रही है ताकि उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सके। इसके अलावा वीडियो में इस्तेमाल किए गए हथियारों के लाइसेंस और वैधता की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में फायरिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बंगाल में टीएमसी पर संकट गहराया

58 बागी विधायक बने प्रमुख विपक्ष

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए चुनौतियाँ लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों सत्ता गंवाने के बाद अब पार्टी को अपने ही विधायकों की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 58 बागी टीएमसी विधायकों को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है।विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र नाथ बोस ने विधायक ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले समूह को आधिकारिक रूप से विपक्षी दल का दर्जा प्रदान किया। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बागी विधायकों का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत तानाशाही शैली में काम कर रहा है और संगठन के भीतर असहमति के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। कई विधायकों ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं।इस राजनीतिक संकट के बीच पार्टी के शहरी नेतृत्व को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, जिन्हें टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है, उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएँ तेज हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने हकीम के इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि अभी तक कोई औपचारिक इस्तीफा कोलकाता नगर निगम को नहीं सौंपा गया है।कोलकाता नगर निगम की अध्यक्ष माला रॉय ने कहा कि उन्हें अभी तक फिरहाद हकीम का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार महापौर को अपना इस्तीफा लिखित रूप से निगम अध्यक्ष को सौंपना होता है।

अमरिंदर सिंह की कांग्रेस वापसी की अटकलों से पंजाब की राजनीति गर्माई

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। कांग्रेस में उनकी संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया है। इन चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अमरिंदर सिंह लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनसे बातचीत की जा सकती है।हुड्डा के इस बयान के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावों को देखते हुए पुराने नेताओं को साथ लाने की रणनीति पर काम कर सकती है। हालांकि कांग्रेस और अमरिंदर सिंह, दोनों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।हाल के दिनों में अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी। उन्होंने बताया था कि परिवार में शोक की घड़ी के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन कर संवेदना व्यक्त की थी। इस बयान को भी राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने महत्वपूर्ण संकेत माना। दूसरी ओर पंजाब भाजपा में हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनसे इस विषय में कोई सलाह नहीं ली गई। भाजपा कार्यालय में नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भी उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही।

देश में मानसून की दस्तक, 24 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार केरल में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार मानसून अगले दो से तीन दिनों के भीतर गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी के अतिरिक्त क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की गतिविधियां तेज होने की संभावना है।मौसम विभाग ने अगले सात दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण तेज आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है। विभाग ने ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना सहित 24 राज्यों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है।विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष मानसून सामान्य तिथि से लगभग तीन दिन देरी से केरल पहुंचा है। सामान्य तौर पर मानसून एक जून को केरल तट पर पहुंचता है और लगभग

डेढ़ महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। इसके बाद सितंबर के मध्य से वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है।आईएमडी ने बताया कि केरल के अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में भारी वर्षा के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि कुछ स्थानों पर 11 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि क्यूम्युलोनिम्बस बादलों की सक्रियता के कारण कई क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।हालांकि मानसून की शुरुआत के बावजूद देश के कई हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने से किसानों को राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी।

NEET अभ्यर्थी की मौत पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

बोले- "यह आत्महत्या नहीं, व्यवस्था की विफलता

NEET-UG से जुड़े पेपर लीक, परीक्षा प्रबंधन और परिणामों को लेकर पिछले कुछ महीनों में देशभर में व्यापक विवाद और छात्र आंदोलन हुए हैं।एक अभ्यर्थी की मौत के बाद राहुल गांधी ने इसे शिक्षा व्यवस्था की विफलता बताते हुए केंद्र सरकार पर युवाओं का भविष्य संकट में डालने का आरोप लगाया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) को लेकर जारी विवाद गुरुवार को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। एक NEET अभ्यर्थी की मौत के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह केवल एक छात्र की आत्महत्या नहीं बल्कि एक "टूटी हुई व्यवस्था" का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार परीक्षा विवादों, पेपर लीक और अनिश्चितता ने लाखों छात्रों को मानसिक दबाव में धकेल दिया है।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयान में कहा कि देश के युवाओं का भविष्य लगातार संकट में डाला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा कमजोर हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग की है।दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद करार दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी अनियमितता की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का पक्ष है कि शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।NEET-UG पेपर लीक और अन्य परीक्षा विवादों को लेकर हाल के दिनों में छात्र संगठनों द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। विपक्षी दल इन आंदोलनों को युवाओं की वास्तविक चिंता बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षा और रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में विपक्ष और सरकार के बीच प्रमुख राजनीतिक संघर्ष का विषय बन सकता है। युवाओं की बड़ी आबादी वाले देश में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता अब एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरती दिखाई दे रही है।

गाजा में फिर तेज हुए हवाई हमले, युद्धविराम की कोशिशों को झटका

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

गाजा पट्टी में गुरुवार को हुए ताजा हवाई हमलों में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इन घटनाओं ने क्षेत्र में चल रहे युद्धविराम प्रयासों को एक बार फिर झटका पहुंचाया है और मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है।स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार तड़के हुए हवाई हमलों में कई आवासीय इमारतें प्रभावित हुईं। मृतकों में एक ही परिवार के पांच सदस्य भी शामिल बताए जा रहे हैं। हमलों के बाद बचाव दलों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए घंटों तक अभियान चलाया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दीं।गाजा में यह हिंसा ऐसे समय हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्धविराम को स्थायी बनाने के प्रयास कर रहा है। हालांकि पहले हुए समझौतों के बावजूद क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई पूरी तरह बंद नहीं हो सकी है। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि युद्धविराम लागू होने के बाद भी सैकड़ों लोग हिंसा में मारे जा चुके हैं।इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की जा रही है और वह उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान चला रहा है। वहीं फिलिस्तीनी पक्ष का आरोप है कि लगातार सैन्य हमलों के कारण आम नागरिक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों, राहत शिविरों और बुनियादी सुविधाओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।

पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से स्पष्ट रूप से पूछा कि पंचायत चुनाव आखिर कब तक कराए जाएंगे और इसके लिए संभावित समयसीमा क्या है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर लंबे समय तक प्रशासकों के माध्यम से व्यवस्था चलाना उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी जानना चाहा कि पंचायत चुनाव कराने में आखिर कौन सी बाधाएं सामने आ रही हैं और चुनाव कार्यक्रम घोषित करने में इतनी देरी क्यों हो रही है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जा रहा है, जबकि संविधान स्थानीय निकायों के नियमित चुनावों की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।दूसरी ओर राज्य सरकार और चुनाव आयोग की ओर से अदालत को विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। हालांकि अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि चुनावों को अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता। खंडपीठ ने आयोग से अगली सुनवाई में चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।इस मामले के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। पंचायत चुनावों को ग्रामीण राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है और इन्हीं चुनावों के माध्यम से गांव स्तर पर राजनीतिक दलों की पकड़ मजबूत होती है। ऐसे में चुनाव में देरी का मुद्दा अब राजनीतिक दलों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों मतदाता और हजारों संभावित उम्मीदवार अब चुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। गुरुवार की सुनवाई ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका इस मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।

पुतिन के आर्थिक सम्मेलन से पहले यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, रूस की सुरक्षा पर उठे सवाल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने गुरुवार को नया मोड़ ले लिया जब यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। यह हमला ऐसे समय हुआ जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वार्षिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहे थे। इस घटना ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था और युद्ध की बदलती रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन हमलों में सेंट पीटर्सबर्ग के एक प्रमुख तेल टर्मिनल को निशाना बनाया गया, जहां आग लगने की घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा क्रोनस्टाट नौसैनिक अड्डे के आसपास भी विस्फोटों की सूचना मिली। हमलों के बाद कई उड़ानों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया गया तथा सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों को रूस की सैन्य और आर्थिक क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि जब तक रूस यूक्रेन पर हमले जारी रखेगा, तब तक यूक्रेन भी अपनी रक्षा और जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। दूसरी ओर रूस ने इन हमलों को आतंकवादी कार्रवाई बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग राष्ट्रपति पुतिन का गृह नगर है और यहां आयोजित आर्थिक सम्मेलन को रूस अपनी आर्थिक शक्ति और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के प्रदर्शन के रूप में देखता है। हालांकि पश्चिमी देशों की अधिकांश कंपनियां इस मंच से दूर हैं, फिर भी एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन की बढ़ती ड्रोन क्षमता युद्ध के समीकरण बदल रही है। रूस के भीतर गहराई तक पहुंचकर किए जा रहे हमले यह संकेत देते हैं कि संघर्ष अब केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक संरचनाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं।

इजराइल-लेबनान के बीच युद्धविराम पर सहमति

मध्य पूर्व में शांति की नई उम्मीद

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

लंबे समय से तनाव और सैन्य टकराव का सामना कर रहे इजराइल और लेबनान के बीच गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता सामने आई। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों ने युद्धविराम को पुनः लागू करने और सीमा क्षेत्र में शांति बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। इस घटनाक्रम को पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।अमेरिकी विदेश विभाग में कई दौर की वार्ताओं के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि युद्धविराम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह बंद करे और अपने लड़ाकों को लितानी नदी के दक्षिणी क्षेत्रों से हटाए। समझौते के तहत सीमावर्ती इलाकों में विशेष सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे, जहां किसी भी सशस्त्र संगठन की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।पिछले कई महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच रॉकेट

हमलों और जवाबी सैन्य कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव बना हुआ था। कई बार स्थिति पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ती दिखाई दी थी। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में इजराइल द्वारा बेरूत पर संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद कूटनीतिक समाधान का रास्ता निकला। लेबनान सरकार ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि देश लंबे समय से संघर्ष और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इसलिए स्थिरता बहाल होना आवश्यक है। वहीं इजराइल ने स्पष्ट किया है कि यदि समझौते की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस युद्धविराम के क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं।

संपादक की कलम से

पानी जीवन का आधार है। मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पर्यावरण सभी की निर्भरता जल पर है। इसके बावजूद आज दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, भूजल के अत्यधिक दोहन और जल स्रोतों के प्रदूषण ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। ऐसे समय में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकता बन चुका है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों की जल आवश्यकताएं मानसून पर निर्भर हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है तो कहीं सूखे जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इससे जल संसाधनों का संतुलन बिगड़ रहा है। कई शहरों और गांवों में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट आम बात हो गई है। यह संकेत है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में समस्या और गंभीर हो सकती है।जल संरक्षण की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर से की जा सकती है। घरों में पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को अपनाना और जल के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना आवश्यक है। छोटी-छोटी बचत भी बड़े परिणाम दे सकती है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग जल की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है।सरकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जलाशयों, तालाबों और नदियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियां लागू करनी होंगी। शहरी क्षेत्रों में जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित करना भी समय की मांग है। जल संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। पानी की कमी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है, उद्योगों की गति को धीमा करती है और लोगों के जीवन स्तर पर सीधा असर डालती है। इसलिए जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है।आज यदि हम पानी बचाने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। जल की हर बूंद अनमोल है और उसका संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का सबसे प्रभावी मार्ग है।

अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग तेज

यूपी की राजनीति में बढ़ा सियासी तापमान

लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और भाजपा तथा समाजवादी पार्टी के बीच 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों दल एक-दूसरे के शासन और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को उस समय नया विवाद खड़ा हो गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर तीखा हमला बोला। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी का यह दौर पिछले कुछ दिनों से जारी था, लेकिन गुरुवार को यह विवाद और अधिक चर्चा में आ गया। राजनीतिक जानकार इसे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में तेज हो रही राजनीतिक सक्रियता का संकेत मान रहे हैं।विवाद की शुरुआत हाल ही में हुई एक सार्वजनिक चर्चा से हुई थी, जिसमें उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की राजनीति, उसके पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले और विपक्षी रणनीति पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, किसानों को उचित मूल्य और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि इन मुद्दों पर सरकार सफल होती तो उसे विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे, निवेश, कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केवल बयानबाजी के माध्यम से राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है।इस राजनीतिक टकराव के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। दोनों दलों के समर्थकों ने अपने-अपने नेताओं के पक्ष में अभियान चलाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक दल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि दोनों दल जनता से जुड़े मुद्दों पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। गुरुवार को सामने आई यह जुबानी जंग भी उसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसने प्रदेश की राजनीति का तापमान एक बार फिर बढ़ा दिया है।

अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर कांग्रेस का हमला तेज, इस्तीफे की मांग

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

अरुणाचल प्रदेश की राजनीति गुरुवार को उस समय गरमा गई जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ अपना हमला और तेज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के बीच मुख्यमंत्री का पद पर बने रहना लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अनादर दर्शाता है।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को नैतिक आधार पर जवाब देना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री को पद छोड़ना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि जनता के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश देने के लिए यह आवश्यक कदम है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि यदि आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगी।वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष बिना तथ्यों के राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा का दावा है कि राज्य सरकार विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विपक्ष मुद्दाविहीन होकर आरोपों की राजनीति कर रहा है।अरुणाचल

प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क और सीमा क्षेत्रों के विकास को लेकर कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। भाजपा इन उपलब्धियों को अपनी प्रमुख ताकत के रूप में पेश कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस राज्य में राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में उठे इस विवाद का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस को नया आयाम दे सकता है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है।

INDIA गठबंधन में टीएमसी की भूमिका पर अटकलें

विपक्षी राजनीति में बढ़ी हलचल

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

विपक्षी राजनीति में गुरुवार को उस समय नई चर्चा शुरू हो गई जब INDIA गठबंधन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की भूमिका और प्रभाव को लेकर अटकलें तेज हो गईं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि गठबंधन के भीतर तृणमूल कांग्रेस की स्थिति आने वाले समय में किस प्रकार प्रभावित होगी।तृणमूल कांग्रेस वर्तमान में INDIA गठबंधन के प्रमुख घटकों में से एक है और संसद में उसकी संख्या विपक्ष की ताकत को प्रभावित करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी की आंतरिक या क्षेत्रीय राजनीतिक चुनौतियां बढ़ती हैं तो इसका असर व्यापक विपक्षी रणनीति पर भी पड़ सकता है।गठबंधन के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में विभिन्न संभावित समीकरणों पर चर्चा जारी है। विपक्षी दलों के सामने चुनौती यह है कि वे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाए रखें और साथ ही अपने-अपने राज्यों की राजनीतिक

परिस्थितियों का भी सामना करें।भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्षी गठबंधन वैचारिक रूप से असंगत है और विभिन्न दल केवल चुनावी मजबूरी में साथ आए हैं। दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए विपक्षी एकता आवश्यक है।विशेषज्ञों के अनुसार 2026 के दौरान होने वाले विभिन्न राज्य चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रम INDIA गठबंधन की वास्तविक मजबूती की परीक्षा साबित हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति और उसके सांसदों की भूमिका पर नजर रखने के पीछे यही कारण है। फिलहाल गठबंधन में किसी टूट या बड़े बदलाव का संकेत नहीं मिला है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं ने विपक्षी खेमे की रणनीति को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।

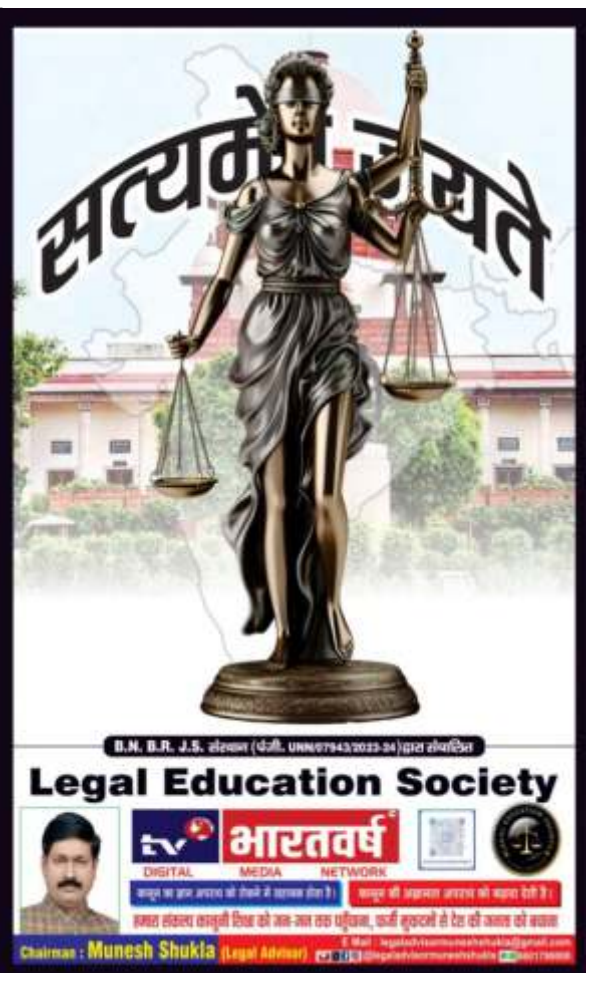

बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बड़े बदलाव

अभ्यर्थियों को दो प्रवेश पत्र लाने होंगे

उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर इस बार प्रशासन और परीक्षा नियामक संस्थाओं ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार को डीएसएन डिग्री कॉलेज में एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों, केंद्राध्यक्षों, कक्ष निरीक्षकों और विश्वविद्यालय पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।बैठक की अध्यक्षता सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने की। इस दौरान परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर दो प्रवेश पत्र लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा। इनमें से एक प्रवेश पत्र अभ्यर्थी की उपस्थिति और पहचान सत्यापन के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि दूसरा प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र के अभिलेखों और प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों की पहचान प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सख्त बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से रोका जा सकता है।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन तथा अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित दस्तावेज और आवश्यक सामग्री के साथ ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की जाएगी ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा सके।प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों ने केंद्राध्यक्षों और कक्ष निरीक्षकों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता या अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी परीक्षा संचालन में दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कठोर कदम समय की आवश्यकता हैं। उनका कहना है कि तकनीकी निगरानी, सख्त पहचान सत्यापन और सुरक्षा प्रबंधों से परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा और मजबूत होगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इन नई व्यवस्थाओं के माध्यम से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराया जा सकेगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग तेज

देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे विवादों के बीच छात्र संगठनों ने गुरुवार को परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और पारदर्शिता की मांग को फिर जोरदार ढंग से उठाया। कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि हाल के वर्षों में परीक्षा स्थगन, तकनीकी गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया है।छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़ी होती हैं, इसलिए इनकी विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि परीक्षा संचालन में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए और किसी भी अनियमितता की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।शिक्षा विशेषज्ञों ने भी माना कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि डिजिटल निगरानी, सुरक्षित प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली और जवाबदेही तय करने से विवादों को कम किया जा सकता है।केंद्र और राज्य सरकारें भी परीक्षा सुधारों को लेकर विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं। हाल के वर्षों में कई नई तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, लेकिन छात्र संगठनों का कहना है कि अभी और सुधार की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे युवा देश में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे केवल प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक महत्व के मुद्दे भी हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना समय की मांग है।

Best Economy in IPL

कुंबले के नाम है सबसे अच्छी इकॉनमी

भारतीय क्रिकेट टीम में युवा खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों को देखते हुए चयन समिति ने गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और भविष्य की टीम रणनीति को लेकर व्यापक चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में अवसर मिलने की संभावना है।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों का कहना है कि टीम प्रबंधन अगले विश्व टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में घरेलू क्रिकेट से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं, जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।बैठक में बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और ऑलराउंडर विकल्पों पर विशेष चर्चा हुई। चयनकर्ताओं का मानना है कि टीम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव देना आवश्यक है। साथ ही वरिष्ठ खिलाड़ियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनी रहेगी।क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय क्रिकेट इस समय प्रतिभा के मामले में दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शामिल है। घरेलू टूर्नामेंटों और आईपीएल ने खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का बड़ा मंच दिया है। यही कारण है कि चयनकर्ताओं के सामने विकल्पों की कमी नहीं है।आने वाले दिनों में संभावित टीम की घोषणा होने की उम्मीद है। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस बात पर है कि किन युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलती है और कौन-कौन से अनुभवी खिलाड़ी अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहते हैं।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई दौरे की शानदार शुरुआत की

भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने एशियाई दौरे की शुरुआत शानदार प्रदर्शन के साथ करते हुए प्रतिद्वंद्वी टीम पर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक और संतुलित खेल का प्रदर्शन किया, जिससे टीम प्रबंधन और खेल विशेषज्ञों के बीच उत्साह का माहौल है। इस मुकाबले में युवा खिलाड़ियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया और यह संकेत दिया कि भारतीय हॉकी का भविष्य मजबूत हाथों में है।मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। मध्य पंक्ति के खिलाड़ियों ने तेज पासिंग और आक्रमण की रणनीति के जरिए विपक्षी रक्षा पंक्ति पर लगातार दबाव बनाया। पहले हाफ में ही भारत ने बढ़त हासिल कर ली और इसके बाद विपक्षी टीम वापसी नहीं कर सकी।मुख्य कोच ने मैच के बाद कहा कि टीम पिछले कई महीनों से फिटनेस और रणनीतिक तैयारी पर विशेष ध्यान दे रही थी। युवा खिलाड़ियों को लगातार अवसर दिए जा रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम मैदान पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को देखते हुए यह जीत खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ओलंपिक और अन्य प्रमुख प्रतियोगिताओं में मिली सफलताओं ने टीम को नई पहचान दी है। गुरुवार का प्रदर्शन इसी निरंतर सुधार का प्रमाण माना जा रहा है। अब टीम की नजर आगामी मुकाबलों पर है, जहां उसे और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना होगा। यदि खिलाड़ी इसी लय को बरकरार रखते हैं तो आने वाले महीनों में भारत अंतरराष्ट्रीय हॉकी में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है।

विराट कोहली और फैंस को लगा करारा झटका

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का आगाज होने वाला है। पहले 6 जून से टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 13 जून से तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान पहले ही कर दिया है। इस बीच अचानक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। पता चला है कि टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा है। विराट कोहली लंबे समय बाद टीम इंडिया के लिए खेलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन खुद कोहली और उनके फैंस को करारा झटका लगा है। अब विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। विराट कोहली अभी कुछ दिन पहले तक आईपीएल में आरसीबी के लिए खेल रहे थे। गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में कोहली ने धमाकेदार पारी खेली थी और छक्का लगाकर अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने में कामयाबी हासिल की थी। बीसीसीआई के एक सोर्स ने PTI को बताया कि कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण ODI सीरीज से बाहर हैं। उनकी गैरमौजूदगी में आने वाली सीरीज की चमक फीकी पड़ जाएगी। हालांकि भारत के पूर्व कप्तान कोहली अब एक फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन वह दुनिया भर के फैंस के लिए टॉप अट्रैक्शन बने हुए हैं। अभी उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। आईपीएल खत्म होने के बाद अहमदाबाद से कोहली सीधे आगरा पहुंचे और वहां से वृंदावन आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी थीं और दोनों ने वहां पर प्रेमानंद महाराज के दरवार में पहुंचे थे। इसकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।

कोहली और अनुष्का मुंह पर मास्क लगाकर वहां पहुंचे थे, ताकि ज्यादा लोग उन्हें पहचान ना पाएं। माना ये जा रहा था कि कोहली वनडे सीरीज से पहले प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने वहां पहुंचे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है, उसने फैंस के दिल को तोड़ दिया है।

सिंगापुर का वीडियो चर्चा में

रात 1 बजे खाली सड़क, फिर भी नहीं तोड़ी रेड लाइट

किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतों या चमकदार सड़कों से नहीं बनती, बल्कि वहां के लोगों की छोटी-छोटी आदतें भी बहुत कुछ बताती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रात के 1 बजे एक शख्स खाली सड़क होने के बावजूद पैदल यात्रियों के लिए हरी बत्ती का इंतजार करता नजर आता है. सिंगापुर में रहने वाली भारतीय महिला कृतिका जैन ने यह वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा कि मुझे नहीं पता कि यह आदत है, अनुशासन है या फिर लोगों की सोच का हिस्सा. यह बहुत छोटी-

सी बात है, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है. वीडियो में एक अकेला पैदल यात्री रात के सन्नाटे में सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है. सड़क लगभग खाली है और आसपास कोई खास ट्रैफिक भी नजर नहीं आता. इसके बावजूद वह शख्स सड़क पार नहीं करता और सिग्नल के हरा होने का इंतजार करता है. ⓘ

उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला

शख्स की फ्लाइट छूटी तो रेलवे ने चुकाई कीमत

भारत में ट्रेनों का लेट होना अक्सर सामान्य बात मान ली जाती है. ज्यादातर यात्री इसे अपनी मजबूरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन राजस्थान के कोटा में रहने वाले एक कपल ने ऐसा नहीं किया. ट्रेन की देरी की वजह से उनकी फ्लाइट छूट गई, जिसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार रेलवे से मुआवजा हासिल कर लिया.

यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक यात्री ने ट्रेन की देरी से हुए नुकसान का हिसाब मांगा और उपभोक्ता आयोग से अपने पक्ष में फैसला भी हासिल किया. कोटा निवासी अनिल कुमार राणा और उनकी पत्नी अनीता

राणा ने दिसंबर 2017 में केरल यात्रा की योजना बनाई थी. इसके लिए उन्होंने दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट पहले से बुक कर रखी थी. दोनों ने फ्लाइट टिकटों पर 33,929 रुपये खर्च किए थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पहुंचने के लिए उन्होंने कोटा से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया. ट्रेन का निर्धारित समय ऐसा था कि उनके पास फ्लाइट पकड़ने के लिए पर्याप्त समय बचना था. राजधानी एक्सप्रेस को दोपहर 12:40 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचना था, जबकि उनकी फ्लाइट शाम 6:05 बजे निर्धारित थी. ⓘ

वेदांग-शरवरी की केमिस्ट्री से सजा इश्क मस्ताना

नई दिल्ली। अभिनेता दिलजीत दोसांझ और निर्देशक इम्तियाज अली की बहुप्रतीक्षित फिल्म मैं वापस आऊंगा रिलीज से पहले ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया था और अब इसका नया गीत इश्क मस्ताना भी जारी कर दिया गया है। गाने में वेदांग रैना और शरवरी वाघ की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। साल 1947 के भारत-विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में वेदांग रैना दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के युवा किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी इतिहास, भावनाओं और मानवीय रिश्तों के ताने-बाने को बड़े पर्दे पर पेश करती है, जिसके चलते इसे

लेकर दर्शकों में खास उत्सुकता बनी हुई है।

इश्क मस्ताना गीत को मोहित चौहान ने अपनी आवाज दी है। उनके साथ नरगिस तेजी और पूजा तिवारी ने भी स्वर मिलाए हैं। गीत के बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं, जबकि संगीत का जादू एआर रहमान ने बिखेरा है। मधुर धुन और भावनात्मक बोलों के कारण यह गीत श्रोताओं के दिलों को छू रहा है। फिल्म आगामी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इसकी सीधी टक्कर भारत भाग्य विधाता से होगी, जिसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच होने वाला मुकाबला दर्शकों और फिल्म कारोबारियों के लिए खास दिलचस्पी का विषय बना हुआ है।

बंदर को लेकर उठ रहे सवालों पर बोले निर्देशक

निर्देशक अनुराग कश्यप की आगामी फिल्म बंदर अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में बॉबी देओल एक लोकप्रिय टीवी अभिनेता की भूमिका में नजर आएंगे, जिसकी जिंदगी उस समय पूरी तरह बदल जाती है जब उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। ट्रेलर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं, जिनमें इसे मी टू आंदोलन से जोड़कर भी देखा गया। अब इस पर खुद अनुराग कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बातचीत के दौरान अनुराग कश्यप ने स्पष्ट किया कि बंदर का मी टू आंदोलन से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने कहा कि मी टू सत्ता के दुरुपयोग और प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए यौन शोषण से जुड़ा आंदोलन है, जबकि उनकी फिल्म का विषय इससे अलग है। कश्यप के मुताबिक, फिल्म किसी सत्ता संघर्ष या यौन शोषण की कहानी नहीं कहती, इसलिए इसे मी टू के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। वहीं, फिल्म के निर्माता निखिल द्विवेदी ने भी उन आरोपों को खारिज किया, जिनमें फिल्म को महिला विरोधी बताया जा रहा था। गौरतलब है कि, मी

टू आंदोलन ने 2017 में वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान बनाई थी, जब विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के अपने अनुभव सार्वजनिक किए थे। दूसरी ओर बंदर एक अलग सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। फिल्म में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद और राज बी. शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

पहलाज निहलानी: गोविंदा के 'गॉडफादर' से लेकर सेंसर बोर्ड के सबसे चर्चित अध्यक्ष तक का सफर

पहलाज निहलानी को आसान शब्दों में कहें तो वह बॉलीवुड के एक ऐसे पारखी फिल्ममेकर थे जो दर्शकों की नब्ज को बखूबी पहचानते थे। उन्होंने निर्माता के रूप में एक बेहद सफल करियर बनाया और बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। वह 'आंखें', 'शोला और शबनम', 'इल्जाम', 'अंदाज', 'तलाश', 'रंगीला राजा' और 'जूली 2' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। फिल्म निर्माण के अलावा, पहलाज निहलानी की एक और बड़ी पहचान यह भी थी कि उन्होंने साल 2015 से 2017 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उनके इस दो साल के कार्यकाल ने देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। सेंसर बोर्ड के चीफ रहते हुए फिल्मों में कड़े कट्स लगाने और कैंची चलाने के उनके कई फैसलों ने फिल्म जगत में भारी विवाद खड़ा कर दिया था। उस दौरान रचनात्मक स्वतंत्रता, सेंसरशिप की सीमाओं और भारतीय सिनेमा में सेंसर बोर्ड की भूमिका को लेकर पूरी इंडस्ट्री में एक लंबी और तीखी बहस छिड़ गई थी। कई फिल्ममेकर्स उनके कड़े रुख से नाराज भी हुए, लेकिन निहलानी हमेशा अपने नियमों पर अडिग रहे। पहलाज निहलानी का नाम आते ही अभिनेता गोविंदा का चेहरा खुद-ब-खुद सामने आ जाता है। उन्हें गोविंदा का 'गॉडफादर' भी कहा जाता था। उन्होंने ही गोविंदा की शुरुआती करियर की सबसे यादगार और सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, जिसने गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनके द्वारा बनाई गई मसाला फिल्में आज भी सुपरहिट हैं। निहलानी ने 1980 के दशक की शुरुआत में एक फिल्म निर्माता के तौर पर अपने सफर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म 'हथकड़ी' 1982 में रिलीज हुई, जिसके बाद 1985 में 'आंधी-तूफान' आई। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी केरियर में कई पंख जुड़ते गए। साल 2015 से 2017 के बीच पहलाज निहलानी ने सीबीएफसी के चेयरपर्सन बने। वो फिल्म सर्टिफिकेशन और सेंसरशिप को लेकर भी सुर्खियों में छाए रहते थे। बोर्ड का हिस्सा रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिन्होंने इंडस्ट्री के भीतर ही कई चर्चाओं को जन्म दे दिया। कहा जाता है कि वो सीबीए फसी के सबसे चर्चित चीफ रहे हैं। इसके बाद उनकी जगह प्रसून जोशी ने ली जो अब प्रसार भारती के चेयरमैन हैं।

दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकातों से बढ़ी राजनीतिक चर्चा, अटकलों का दौर तेज

लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सभी प्रमुख दल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं।इसी बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।हालांकि भाजपा इसे नियमित संगठनात्मक संवाद बता रही है, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक इन बैठकों को आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मंथन से जोड़कर देख रहे हैं।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की हालिया दिल्ली यात्रा प्रदेश की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़कर देख रहे हैं।जानकारी के अनुसार केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि बैठकों का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन की स्थिति, सरकार की योजनाओं की प्रगति, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विचार-विमर्श हुआ है। भाजपा नेतृत्व लगातार राज्यों में संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है और यहां होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। इसी कारण भाजपा नेतृत्व प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के प्रमुख पिछड़ा वर्ग नेताओं में गिना जाता है और प्रदेश में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनकी दिल्ली यात्रा को सामान्य राजनीतिक गतिविधि से अधिक महत्व दिया जा रहा है।विपक्षी दलों ने भी इन मुलाकातों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी दावा किया कि पार्टी के भीतर संगठनात्मक और राजनीतिक समीकरणों को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और विकास, सुशासन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच काम कर रही है।राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार लोकसभा चुनावों के बाद अब सभी प्रमुख दलों ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा जहां अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी है, वहीं विपक्ष भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच होने वाली मुलाकातें स्वाभाविक रूप से राजनीतिक महत्व रखती हैं।फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली यात्रा और शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। आने वाले महीनों में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों से इन मुलाकातों के वास्तविक राजनीतिक संकेत और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों के लिए यह घटनाक्रम विशेष रुचि का विषय बना हुआ है।

आयुष्मान कार्ड घोटाले का आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा बड़ा नेटवर्क उजागर

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े से जुड़े एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एसटीएफ ने राजधानी लखनऊ से एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हजारों लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी योजना का लाभ लेने की साजिश रची थी।एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से फर्जी लाभार्थी तैयार करने वाले नेटवर्क का हिस्सा था। पूछताछ के दौरान उसने करीब 1,500 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्ड तैयार कराने में अपनी भूमिका स्वीकार की है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस नेटवर्क के तार प्रदेश के कई जिलों तक फैले हो सकते हैं।आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा योजना का दुरुपयोग कर सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। एसटीएफ को पिछले कुछ समय से इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई और तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपी तक पहुंचा गया।गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से कई दस्तावेज, मोबाइल फोन, कंप्यूटर डेटा और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। इनकी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य राज्यों में भी जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

टीजीटी परीक्षा में चार फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार बायोमेट्रिक जांच में खुला राज

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और नकलमुक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच राजधानी लखनऊ में आयोजित टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परीक्षा के विभिन्न केंद्रों पर जांच के दौरान चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। घटना के बाद परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है।जानकारी के अनुसार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन और बायोमेट्रिक मिलान किया जा रहा था। इसी दौरान अधिकारियों को कुछ अभ्यर्थियों की पहचान को लेकर संदेह हुआ। जब उनके आधार कार्ड, फोटो और बायोमेट्रिक विवरण की जांच की गई तो पता चला कि वे वास्तविक अभ्यर्थी नहीं हैं। इसके बाद उन्हें तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि आरोपी संगठित तरीके से परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई गिरोह सक्रिय है या नहीं। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। इनके माध्यम से अन्य संदिग्ध लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए इस बार कई तकनीकी उपाय लागू किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो मिलान और पहचान पत्र की जांच अनिवार्य की गई थी।

इसी कारण फर्जीवाड़े का प्रयास समय रहते पकड़ लिया गया।घटना के बाद परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट और चुनाव कार्यक्रम पर मांगा जवाब

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी है। अदालत ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही पंचायत चुनाव कराने की संभावित समयसीमा भी स्पष्ट करने को कहा है।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने पूछा कि चुनाव कराने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और चुनाव कार्यक्रम कब तक घोषित किया जा सकता है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस संबंध में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।गौरतलब है कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चा और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इसी कारण चुनाव कार्यक्रम घोषित होने में देरी हुई है। कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने समय पर चुनाव कराने की मांग उठाई है।विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकास की आधारशिला मानी जाती है। ऐसे में चुनावों में देरी का असर स्थानीय प्रशासनिक और विकास कार्यों पर पड़ सकता है। वर्तमान में कई स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालित किए जा रहे हैं।राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावों में अनावश्यक देरी की जा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।हाईकोर्ट की अगली सुनवाई में राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पंचायत चुनावों की दिशा और संभावित कार्यक्रम को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। प्रदेश के लाखों मतदाता और जनप्रतिनिधि अब अदालत और निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर नजर बनाए हुए हैं।

पेपर लीकमें शामिल होने पर कुर्क होगी संपत्ति

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी पुलिस में बंपर पदों पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में सेंधमारी करने वाले किसी भी सॉल्वर या नकल माफिया को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी या सॉल्वर इस परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ नए और सख्त कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों में जो भी विवेचक (इन्वेस्टिगेटर) होगा, वह अपनी रिपोर्ट सीधे संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) को भेजेगा। बोर्ड की तरफ से जारी चेतावनी में कहा गया है कि परीक्षा की शुचिता भंग करने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऐसे अपराधियों से परीक्षा आयोजित कराने में हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। पकड़े जाने पर लंबी जेल और भारी जुर्माने का भी कड़ा प्रावधान लागू किया जाएगा। बता दें कि 'यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024' के तहत ऐसी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में होंगे विशेष कार्यक्रम

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा।सरकारी सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, गरीब कल्याण कार्यक्रमों और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिलास्तर पर भी जनसंवाद और जागरूकता कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है।मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों से कहा कि वृक्षारोपण केवल औपचारिकता न रहे बल्कि लगाए गए पौधों के संरक्षण की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें योगदान देना चाहिए।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों को भी प्राथमिकता देने का संदेश देना चाहती है। दूसरी ओर विपक्ष इन कार्यक्रमों को राजनीतिक दृष्टि से भी देख रहा है और सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है।प्रदेश सरकार का कहना है कि जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और विकास योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। प्रशासन ने सभी जिलों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

वाराणसी जेल में आरोपी की मौत से बवाल परिजनों ने जेल गेट पर किया प्रदर्शन

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के निहालीखेड़ा निवासी राहुल निषाद की वाराणसी जेल में मौत हो गई। वह दुष्कर्म और मारपीट के मामलों में आरोपी था। परिजनों ने जिला कारागार के बाहर हंगामा किया। उन्होंने जेल प्रशासन पर यातनाएं देने और हत्या का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि राहुल को ढाई बीघा जमीन के विवाद में फंसाया गया था। उस पर 2021 से 2025 के बीच दुष्कर्म के चार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न व मारपीट के चार मुकदमे दर्ज हुए थे। राहुल को आठ महीने पहले बांगरमऊ से गिरफ्तार किया गया था। चाचा राजू ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में उसे जमानत मिल गई थी। हालांकि अन्य मामलों में जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। उन्होंने जेल में राहुल को यातनाएं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उसे करंट लगाया गया और तन्हाई में रखा गया। बाद में उसे मानसिक बीमार बताकर 24 मार्च को वाराणसी जेल स्थानांतरित किया गया। मंगलवार शाम करीब सात बजे राहुल ने अपने चाचा जगदीश से फोन पर बात की थी। उस समय उसने कोई बीमारी या दिक्कत नहीं बताई थी। उसी रात 12:07 बजे उसकी बनारस जेल में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने बुधवार दोपहर 12 बजे मौत की सूचना दी। परिजनों ने इसे जेल प्रशासन की सोची समझी साजिश बताया। राहुल की मौत से उसकी मां कुंती और अन्य परिजन बेहाल हैं। राजू ने बताया कि गांव के एक व्यक्ति ने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। यह सब ढाई बीघा जमीन पर कब्जे के विवाद के कारण हुआ। राहुल खेती और संपत्ति के कारोबार का काम करता था। प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था। उसके विपक्षी उसे प्रतिद्वंद्वी मानने लगे थे। इसी कारण उसे मुकदमों में फंसाया गया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर उत्पीड़न और प्रताड़ना के बाद हत्या कराने

का आरोप लगाया। उन्होंने जेल अधिकारियों की फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग और जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की मांग की। जेल के बाहर हंगामे की सूचना पर कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को शांत कराने का प्रयास किया। शाम तीन बजे शुरू हुआ हंगामा देर शाम सात बजे तक चला। सदर विधायक पंकज गुप्ता भी वहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों और जेल के अधिकारियों से बात की। परिजन राहुल के शव का उन्नाव में शव परीक्षण कराने की मांग कर रहे थे। विधायक पंकज गुप्ता ने जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से इस प्रकरण पर बात की। उन्होंने परिवार की शंकाओं के समाधान के लिए जांच की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच कराने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि राहुल पर दर्ज मुकदमों की जांच होगी। जेल भेजने और जेल में उसके साथ हुए बर्ताव की भी गहन जांच कराई जाएगी।

उन्नाव में अधिवक्ता भवन निर्माण मामले में रिश्वतखोरी का आरोप

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में सीओ सिटी से मुलाकात कर अधिवक्ता भवन निर्माण मामले की जांच कर रहे विवेचक को हटाने की मांग उठाई। अधिवक्ताओं ने विवेचक पर रिश्वत लेकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार, कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधाओं के लिए राजा राव राम बक्श, आचार्य चाणक्य और परशुराम अधिवक्ता भवनों का निर्माण कराया गया था। वर्तमान बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने पूर्व कार्यकारिणी पर इन भवनों के निर्माण में वित्तीय अनियमितता और घालमेल के आरोप लगाए हैं। इसी संबंध में दर्ज मुकदमे में पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला और पूर्व महामंत्री अरविंद कुमार दीक्षित नामजद हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अपराध संख्या 1052/2025 के तहत दर्ज यह मुकदमा तथ्यों से परे और दुर्भाविनापूर्ण है। पूर्व पदाधिकारियों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विवेचक ने निष्पक्षता के बजाय पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और जल्दबाजी में आरोप पत्र दाखिल करने का प्रयास किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि विवेचक ने पूर्व महामंत्री के भाई से कथित रूप से रिश्वत लेकर मामले में पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाया। अधिवक्ताओं ने मांग की कि जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान विवेचक को हटाकर किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपी जाए। उनका कहना है कि मौजूदा जांच अधिकारी के रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है।

उन्नाव में 8, 9 और 10 जून को होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली

उन्नाव में 8, 9 और 10 जून को होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिलकर परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने बताया कि जनपद में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के लिए कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 3,682 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। बैठक में परीक्षा संचालन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक इंतजामों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को परीक्षा के दौरान पूरी सतर्कता और निष्पक्षता बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में ट्रेजरी का निरीक्षण कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। प्रश्नपत्रों के सुरक्षित रख-रखाव और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। यह क्रम तीनों दिन जारी रहेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उन्नाव पहुंचेंगे, जिसके मद्देनजर उनके आवागमन और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।

उन्नाव की रहने वाली युवती की कानपुर में हत्या नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव की रहने वाली युवती की कानपुर में हत्या कर उसके शव को बुलंदशहर में फेंक दिया गया। इसके पहले युवती ने सदर कोतवाली में तहरीर देखकर नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन सदर कोतवाली पुलिस की लापरवाही युवती के लिए जानलेवा बन गई। मृतका की मां ने इस संबंध में कानपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। कानपुर पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। नर्सिंग होम संचालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र की रहने वाली युवती सदर कोतवाली क्षेत्र के पीडी नगर नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 2 वर्ष पहले 10 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा में स्थित उत्तम हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए गई थी। इसी दौरान युवती की मुलाकात अस्पताल के संचालक देवकांत उत्तम से हुई। उपचार के दौरान ही देवकांत उत्तम में युवती का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बातचीत करने लगा। नर्सिंग होम संचालक बातचीत के दौरान युवती को शादी का झांसा देकर गलत काम किया। उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बना लिए। यहीं से युवती का वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर शोषण करने लगा। नर्सिंग होम संचालक युवती को मध्य प्रदेश के ओरछा, कानपुर, उन्नाव के फ्लैट में ले जाकर भी गलत काम किया गया। 2 साल में युवती दो बार गर्भवती हुई, जिसका गर्भपात करा दिया गया। इस संबंध में युवती ने सदर कोतवाली में 19 मई को शिकायती पत्र देकर नर्सिंग होम संचालक देवकांत उत्तम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन पुलिस से न्याय नहीं मिला। लेकिन पुलिस की लापरवाही युवती के लिए जानलेवा हो गई। 23 मई को बुलंदशहर में युवती की लाश मिली। सदर कोतवाली पुलिस ने 24 मई को मुकदमा दर्ज किया। दूसरी तरफ कानपुर बर्रा थाना पुलिस ने कानपुर में खुलासा करते हुए उत्तम नर्सिंग होम के संचालक देवकांत उत्तम, उसके भतीजे विवेक पटेल और नर्सिंग होम के सिक्योरिटी गार्ड अजीत सिंह को गिरफ्तार किया।

उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र में किसान की करंट लगने से मौत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना कोदईया खेड़ा गांव में गुरुवार को हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय हरिपाल पुत्र स्वर्गीय सिद्धनाथ के रूप में हुई है। वह कोदईया खेड़ा मजरा त्रिपुरारपुर, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव के निवासी थे। हरिपाल पेशे से किसान थे और खेती-किसानी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी एक विवाहित बेटी है।

परिजनों के अनुसार, गुरुवार को हरिपाल अपने घर पर पंखा लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि वह पंखे या बिजली के तार की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए। तेज करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद हरिपाल को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू की। परिजन जिला अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां वे काफी व्यथित थे। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मृतक के रिश्तेदार और अधिवक्ता अमरनाथ यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हरिपाल बिजली के तार और पंखे से संबंधित कार्य करते समय करंट की चपेट में आए थे। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला करंट लगने से मौत का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी आईडी से शातिर ने ठगी का बिछाया जाल

ल रूप से सवोZदयनगर के रहने वाले उन्नाव के पुरवा एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की फर्जी फेसबुक आईडी से शातिर ने कई लोगों से ठगी का प्रयास किया। उसने संतोष कुमार को सीआरपीएफ अधिकारी बताकर फेसबुक दोस्तों को मैसेज किया। कहा इन्होंने चार महीने पहले फ्रीज, टीवी, एसी, एलईडी, सोफा, बेड और अन्य सामान खरीदा था। अब इनका ट्रांसफर हो गया है। 95 हजार में सारा सामान घर भिजवा देंगे। एसडीएम को जैसे ही घटना की जानकारी हुई, उन्होंने एनसीआरपी की हेल्पलाइन पर शिकायत की।बुधवार की शाम करीब सात बजे पुरवा एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव के नाम से उनके फेसबुक दोस्तों के पास मैसेज आए। उसमें लिखा था सीआरपीएफ अधिकारी संतोष कुमार मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह लखनऊ एयरपोर्ट में तैनात थे। इनका ट्रांसफर हो गया है। इन्होंने चार महीने पहले ही फ्रीज, एसी, एलईडी, बेड, सोफा, डायनिंग टेबल, अलमारी समेत अन्य सामान खरीदा था। ट्रांसफर होने की वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है। सारा सामान बेहतर हालत में है। केवल 95 हजार रुपये में यह घर तक पहुंच जाएगा। मैसेज आने पर कुछ दोस्तों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने ओके लिखा। कानपुर के एक युवक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। थोड़ी देर में उनके पास व्हाट्सएप कॉल आई। उसकी डीपी में सीआरपीएफ अधिकारी की यूनीफार्म में कोई नजर आ रहा था। उसने स्वयं को सीआरपीएफ अधिकारी संतोष कुमार बताया। युवक ने जैसे ही सामान की जानकारी की तो दूसरी ओर से फ्रीज, टीवी, सोफा समेत सभी की फोटो भेज दी गई। युवक ने रुपये देने का जरिया पूछा, जिस पर शातिर ने उनके कानपुर के घर का पता पूछा। कहा सीआरपीएफ के दो अफसर घर तक सामान पहुंचा देंगे। युवक ने एसडीएम को मामले की जानकारी दी। उन्होंने देखा और तुरंत फेसबुक पर लिखा कि यह कोई साइबर अपराधी है। इस मैसेज को ध्यान न दें। उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत की। साइबर अपराधी ने एसडीएम का नाम मैसेंजर में हिंदी में प्रमेश कुमार लिखा था, जबकि उनकी वास्तविक आईडी अंग्रेजी में बनी हुई है। उनके दोस्तों ने पहली ही बार में ठगी की साजिश पकड़ ली।

200 से अधिक डिप्टी एसपी के तबादले कई जिलों को मिले नए अधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) संवर्ग में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी नवीनतम स्थानांतरण सूची के अनुसार, राज्य में एक साथ 200 से अधिक पुलिस उपाधीक्षकों (डिप्टी एसपी/सीओ) का तबादला कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में दो सौ से अधिक पुलिस उपाधीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, कई जिलों के डिप्टी एसपी बदल दिए गए हैं। जितेंद्र कुमार को शाहजहांपुर का डिप्टी एसपी बनाया गया है। अनुरुद्ध कुमार को महोबा, अभिषेक सिंह को बलरामपुर का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। पंकज पंत को रामपुर का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। शिव ठाकुर को सहारनपुर, अमित कुमार को मीरजापुर का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। पवन कुमार वर्मा को एलआईयू अयोध्या का पुलिस उपाधीक्षक का चार्ज मिला है। रवि प्रकाश सिंह पुलिस उपाधीक्षक फतेहपुर, रत्नेश्वर सिंह को झांसी, अभिषेक कुमार यादव को खीरी, धर्मेंद्र कुमार सिंह को कानपुर देहात, हेमंत उपाध्याय को बरेली को पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, प्रवीण कुमार तिवारी को मथुरा का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। वहीं, हर्षित चौहान को सीतापुर, रविंद्र कुमार सिंह को महराजगंज, मुनीश चंद्र को हापुड़ और रजनीश कुमार उपाध्याय को कासगंज का पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले पिछले महीने सरकार ने 44 एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ASP) का तबादला कर दिया था। इनमें से 33 अधिकारियों को हाल ही में डिप्टी SP से प्रमोट करके एडिशनल SP रैंक दी गई थी और उन्हें नई जगहों पर तैनात किया गया। अभय मिश्रा का तबादला विजिलेंस डिपार्टमेंट से नोएडा कर दिया गया है। स्वयं सिंह को भी प्रमोशन के बाद नोएडा में ही तैनात किया गया था। तनु उपाध्याय को कानपुर में PAC की 37वीं बटालियन में डिप्टी कमांडेंट बनाया गया। इससे पहले वह इसी यूनिट में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम कर रही थीं। श्रेष्ठा ठाकुर को लखनऊ में ATS में ASP के पद पर तैनात किया गया है। उन्हें 'लेडी सिंघम' के नाम से भी जाना जाता है और इससे पहले वह बागपत में ASP के तौर पर तैनात थीं। मूल रूप से उन्नाव की रहने वाली श्रेष्ठा ने साल 2012 में UPPSC की परीक्षा पास की थी। वह पहली बार साल 2017 में सुर्खियों में आई थीं, जब वह बुलंदशहर में CO के पद पर तैनात थीं। उस समय चालान काटने को लेकर एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उनकी तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हो गया था। बाद में उनका तबादला नेपाल सीमा के पास स्थित बहराइच कर दिया गया था।

योगी सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी वकीलों की फीस में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सरकारी वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उनकी फीस में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को इस फैसले की जानकारी सामने आने के बाद प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है।सरकार के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में राज्य का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। लंबे समय से फीस बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।नई व्यवस्था के तहत रिटेनरशिप शुल्क और प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस दोनों में वृद्धि होगी। सरकार का मानना है कि इससे योग्य अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और अदालतों में राज्य का पक्ष अधिक प्रभावी ढंग से रखा जा सकेगा।विधि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह संशोधन लंबे समय बाद किया गया है। बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती पेशेवर लागत को देखते हुए यह कदम आवश्यक माना गया।कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकारी मुकदमों की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विपक्षी दलों ने पूछा है कि क्या आम नागरिकों को न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी समान स्तर पर संसाधन बढ़ाए जाएंगे।फिलहाल यह निर्णय प्रदेश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में माना जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव अदालतों की कार्यप्रणाली पर भी दिखाई दे सकता है।

यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा स्पष्ट रोडमैप

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जाएंगे और इसके लिए क्या समयसीमा तय की गई है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कार्य कराना उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं और इनके चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए।याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई स्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। अदालत ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है।राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावों में देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग पर जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का दबाव बढ़ेगा। प्रदेश के लाखों ग्रामीण मतदाता अब पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का निर्यात पहली बार दो लाख करोड़ रुपये के पार सरकार ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

उत्तर प्रदेश ने आर्थिक क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए पहली बार दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात दर्ज किया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को इसे प्रदेश की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और निर्यातोन्मुखी विकास रणनीति की बड़ी सफलता बताया।अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पादों की मांग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार बढ़ रही है। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और वाराणसी जैसे शहरों ने निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, हस्तशिल्प, चमड़ा, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि को प्रदेश के उद्योगपतियों, उद्यमियों और श्रमिकों की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र वातावरण, बेहतर कानून व्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे ने उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया है।आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात में वृद्धि का सीधा प्रभाव रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास पर पड़ता है। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना और विदेशी निवेश के कारण आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं।विशेषज्ञों के अनुसार यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख निर्यातक राज्यों में और मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। सरकार ने निर्यात को और बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और लॉजिस्टिक सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की है।